



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 10, 2000/आश्विन 18, 1922

No. 135]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2000/ASVINA 18, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2000

सं. टीएएमपी/56/2000-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कंडला पत्तन न्यास द्वारा की गई विलंबित वापसी पर दंडात्मक ब्याज के दावे से संबंधित मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज द्वारा किए गए अभ्यावेदन का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं० टीएएमपी/56/2000-केपीटी

मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसेज

.....

आवेदक

बनाम

कांडला पत्तन न्यास

.....

प्रतिवादी

आदेश

(सितम्बर, 2000 के 26वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला रोक कर रखी गई राशि और/अथवा विलंबित भुगतान पर केपीटी से दंडात्मक ब्याज के दावे के संबंध में मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसेज से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित है।

2 मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसेज ने प्रयोक्ताओं तथा साथ ही महापत्तनों, दोनों पर समान रूप से लागू विलंबित भुगतान/विलंबित वापसी पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर दंडात्मक ब्याज के भुगतान से संबंधित इस प्राधिकरण के दिनांक 4 फरवरी, 2000 के आदेश के आधार पर राहत मांगते हुए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

3. मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :-

- (i) केपीटी ने उनके बारम्बार अनुरोध के बावजूद वर्ष 1995 से आगे पत्तन से रवाना हुए पोतों पर देय उसकी वापसी राशियों को रोक रखा था ।
- (ii) केपीटी को पत्तन से पोतों के एक बार रवाना होते ही अधिशेष राशि वापस कर देना चाहिए था । यहां तक कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 4 फरवरी, 2000 के आदेश की प्राप्ति के बाद भी वापसी करने की प्रक्रिया में दिनांक 24 मार्च, 2000 तक विलंब हो गया था । वापसी राशि का चेक वर्ष 1995 से आगे तक अथवा संबंधित पोत के अंतिम समुद्री बकाया बिलों की तारीख से देय ब्याज को छोड़ते हुए दिनांक 31 मार्च, 2000 को जारी किया गया था ।
- (iii) केपीटी ने मात्र इस आधार पर कि वापसी के लिए दिया गया आवेदन न तो महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के आदेश और न ही वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परिपत्र के अनुरूप था; ब्याज का भुगतान करना अस्वीकार कर दिया था । यह सही नहीं है, क्योंकि वापसी योग्य राशि की दिनांक 24 मार्च, 2000 को पुष्टि और/अथवा स्वीकृति दी गई थी । दिनांक 24 मार्च, 2000 को कोई औपचारिकताएं लंबित नहीं थीं, इसलिए, भुगतान की व्यवस्था उस तारीख को की जा सकती थी ।
- (iv) केपीटी आदेश से अवगत था और इसलिए 30 दिनों की अवधि के भीतर वर्ष 1995 और 1997 के लिए पुरानी वापसियों को दिनांक 24 मार्च, 2000 से बहुत पहले अंतिम रूप दिया जा सकता था ।
- (v) दिनांक 24/3/2000 से 31/3/2000 तक सात दिनों के लिए 1,47,321 रुपए पर उपचित ब्याज का भुगतान किया जाए ।

4. मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर केपीटी से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है :-

- (i) मैसर्स एशिया शिपिंग पत्तन का एक नियमित प्रयोक्ता है और विभिन्न पत्तन सेवाओं के लिए एक यातायात जमा खाता रख रहा है । पार्टी ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 1999 के आवेदन द्वारा वर्ष 1991 से आगे की अवधि के संबंध में अपने खाते में उपलब्ध शेष की, उसका ब्यौरा प्रस्तुत किए बिना वापसी के लिए आवेदन दिया ।
- (ii) केपीटी द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध पर मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज ने वर्ष 1991 से आगे की अवधि के लिए दावे का विवरण दिनांक 27 जनवरी, 2000 को प्रस्तुत किया था । संवीक्षा करने पर यह देखा गया था कि सभी दावों को वर्ष 1995 से आगे की अवधि से संबंधित 1,47,231/-रुपए के पांच समुद्री यात्रा लेखों को छोड़कर भावी सेवाओं के लिए समायोजित किया गया था । तदनुसार, दावों पर कार्यवाही की गई थी और दिनांक 29 मार्च, 2000 को एक चेक जारी किया गया था । यह चेक पार्टी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2000 को प्राप्त किया गया था ।
- (iii) दिनांक 24 मार्च, 2000 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि अर्थात् सात दिनों के लिए ब्याज के भुगतान का पार्टी का अनुरोध इस तथ्य को देखते हुए कि शेष राशि चालू खाते के रूप में जमा खाते में संग्रहित की गई थी और जब पार्टी ने वापसी के लिए अनुरोध किया था तब उसे संगत दस्तावेजों की प्रस्तुति पर उचित समय के भीतर अंतिम रूप दे दिया गया था, उचित प्रतीत नहीं होता ।

5. मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज ने केपीटी से प्राप्त टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है :-

- (i) यह सही नहीं है कि एक यातायात जमा खाता रखा जाता है । उन्होंने पोत-वार अग्रिम जमाराशि की व्यवस्था की थी ।

- (ii) यह सही नहीं है कि एक पोत जमाराशि को अगले आने वाले पोत में समायोजित किया जाता है । उनके पास कार्य की अधिक मात्रा नहीं होती और सदैव केपीटी से शेष राशि की वापसी की प्रत्याशा करते हैं ।
- (iii) चेक लिया नहीं गया था, परंतु दिनांक 31 मार्च, 2000 को ही सौंपा गया था ।
- (iv) अगर आवेदन को दिनांक 24 मार्च, 2000 के पूर्व अंतिम रूप दे दिया गया था तो ब्याज के लिए अनुरोध का मुद्दा ही नहीं उठता ।

6. गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने भी केपीटी द्वारा विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । जीसीसीआई ने कहा है कि केपीटी ने यह कहते हुए एक परिपत्र जारी किया है कि विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान इस शर्त के अधीन होगा कि दस्तावेज/वापसी का आवेदन हर प्रकार से पूर्ण हो । जीसीसीआई का यह मत है कि यह वृद्धि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश का प्रयोजन ही समाप्त कर देगी ।

7. जीसीसीआई के अभ्यावेदन पर अपने उत्तर में केपीटी ने कहा है कि वापसी के दावे की सत्यता के सत्यापन के लिए वापसी संबंधी आवेदन के साथ प्रयोक्ता से कई दस्तावेज अपेक्षित होते हैं । जब तक सभी अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते और हर प्रकार से पूर्ण नहीं होते, तब तक किसी वापसी संबंधी दावे पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । परिपत्र में जोड़े गए खण्ड का भी यह अर्थ है कि वापसी संबंधी आवेदन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 55 के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना होता है । केपीटी ने मत व्यक्त किया कि यह खण्ड आदेश के किसी संभावित दुरुपयोग को भी रोकेगा ।

8. इस मामले पर दिनांक 16 सितम्बर, 2000 को एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी । संयुक्त सुनवाई के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :-

#### मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज

- (i) दंडात्मक ब्याज के भुगतान के संबंध में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का दिनांक 4 फरवरी, 2000 का आदेश दिनांक 24 मार्च, 2000 को लागू हुआ था ।
- (ii) वे आदेश के प्रभावी होने के बाद विलंब के लिए ही ब्याज की मांग कर रहे हैं ।
- (iii) वे हमारे आदेशाधीन किसी भूतलक्षी वापसी के लिए दावा नहीं कर रहे हैं ।
- (iv) केपीटी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2000 को भुगतान किया गया । इसमें सात दिनों का विलंब हुआ था । केपीटी को उन सात दिनों के लिए ब्याज का भुगतान करना चाहिए ।
- (v) केपीटी ने उन्हें अपने खाते में शेष राशि को अग्रणीत करने की सुविधा नहीं दी ।

#### कंडला पत्तन न्यास (केपीटी)

- (i) केपीटी केवल 18 प्रतिशत ब्याज प्रभारित कर रहा था । परंतु, दिनांक 24 मार्च, 2000 से उन्होंने सभी बकायों पर प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत ब्याज पर विचार प्रारंभ कर दिया । उन्होंने भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया । उन्होंने उसे केवल नए आगमनों पर लागू किया ।
- (ii) पत्तन को भी देय पहले की राशियों की वसूली में भी विलंब हुआ था । परंतु, उन्होंने ऐसी पुरानी वसूली के मामले में 24 प्रतिशत प्रभारित नहीं किया है ।
- (iii) अगर वे मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज के इस मामले में अपवाद करते हैं तो उन्हें सभी के लिए इस पर विचार करना होगा । उन्होंने कोई विभेद नहीं किया है ।

9. इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में और समग्र रूप से ध्यान दिए जाने के आधार पर निम्नलिखित स्थिति सामने आती है :-

- (i) आवेदक और केपीटी ने दिनांक 24 मार्च, 2000 के पूर्व की अवधि से संबंधित वापसी के दावे की जांच-पड़ताल के समर्थन में अपने संबंधित तर्कों को आगे बढ़ाया है। तथापि, आवेदक ने यह तर्क देते हुए कि इस संबंध में प्राधिकरण का आदेश उस तारीख से लागू हुआ था, दिनांक 24 मार्च, 2000 से प्रारंभ हुए 7 दिनों की अवधि के लिए अपने दावे की विलंबित वापसी पर ब्याज का दावा किया है। ऐसा होते हुए, निर्णय किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 24 मार्च, 2000 से केपीटी द्वारा किए गए कथित 7 दिनों के विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज देय है अथवा नहीं।
- (ii) प्राधिकरण के दिनांक 4 फरवरी, 2000 के आदेश के पूर्व पत्तन द्वारा रोक रखी गई राशि/विलंबित वापसियों के मामले में पत्तन प्रयोक्ताओं को केपीटी द्वारा ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।
- (iii) यह मानना होगा कि आदेश का अभिप्राय पत्तन प्रयोक्ताओं तथा साथ ही पत्तन न्यासों, दोनों द्वारा देय दंडात्मक ब्याज की एकरूपता निर्धारित करना था। दूसरे शब्दों में, यह व्यवस्था किसी भी लेन-देन के संगत दोनों पक्षों के लिए समान आधार प्रदान करने के लिए है।
- (iv) केपीटी ने प्राधिकरण के आदेश के दिनांक 24 मार्च, 2000 से कार्यान्वयन की पुष्टि की है। तथापि, केपीटी ने इंगित किया है कि उलझनों से बचने के लिए इसने दिनांक 24 मार्च, 2000 को अथवा उसके बाद पत्तन पर रुके पोतों से उत्पन्न मामलों से ही आगे आदेश का कार्यान्वयन किया है। यह उल्लेखनीय है कि केपीटी ने भी दिनांक 24 मार्च, 2000 से पूर्व रवाना हुए पोतों से सभी बकाया राशियों पर उसके द्वारा प्राप्तव्य दंडात्मक ब्याज लगाने का अपना दावा छोड़ दिया है।
- (v) केपीटी ने इस आदेश को उसके सही रूप में कार्यान्वित किया है। किसी संक्रमण अवधि में परिवर्तनों के प्रति समायोजित होने के लिए किसी कार्यान्वयनकारी एजेंसी को कुछ शीर्ष-अवधि की अनुमति देना तर्कसंगत हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने पर पार्टी को भुगतान प्रेषित करने में 7 दिनों का विलंब माफ किए जाने योग्य है।
- (vi) जीसीसीआई का विलंबित वापसी पर दंडात्मक ब्याज के भुगतान के लिए केपीटी द्वारा कतिपय शर्तें शामिल किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन बिना किसी गुणावगुण के प्रतीत होता है। केपीटी की यह शर्त कि विलंबित वापसियों पर ब्याज का भुगतान दस्तावेजों/वापसी के आवेदन के हर प्रकार से पूर्ण होने के अधीन होगा, शामिल करने का तर्क उचित और इस प्राधिकरण के सख्तीपूर्वक अपने विचार के अनुसार प्रतीत होता है। पत्तन केवल तभी वापसी के दावों की जांच-पड़ताल कर सकता है, जब ऐसे दावे हर प्रकार से पूर्ण हों। तथापि, केपीटी की ओर से यह उचित होगा अगर यह वापसी को और वापसी के दावों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची पूरी करने के लिए औपचारिकताओं के बारे में व्यापारिक प्रयोक्ताओं को अधिसूचित करता है।

10. इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से प्राधिकरण मैसर्स एशिया शिपिंग सर्विसिज द्वारा दिया गया अभ्यावेदन अस्वीकृत करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/143/2000/असा.]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2000

**No. TAMP/56/2000-KPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by M/s. Asia Shipping Services relating to a claim of penal interest on delayed refunds made by the Kandla Port Trust, as in the Order appended hereto.

**SCHEDULE**

**Case No. TAMP/56/2000 - KPT**

**M/s. Asia Shipping Services**

**... Applicant**

**Vs.**

**The Kandla Port Trust**

**... Respondent**

**ORDER**

( Passed on this 26th day of September 2000 )

This case relates to a representation from M/s Asia Shipping Service relating to a claim of penal interest from the KPT on the withheld amount and / or delayed payment

2. M/s Asia Shipping Services have submitted their representation seeking relief on the basis of this Authority's Order dated 4 February 2000 relating to payment of penal interest @ 24% per annum on delayed payments / delayed refunds equally applicable for both users as well as Major Ports.

3. The salient points of the representation made by M/s Asia Shipping Services are given below:

- (i). The KPT had withheld its refunds due on vessels sailed from the Port from 1995 onwards inspite of their repeated request.
- (ii). The KPT should have refunded the surplus amount once the vessel sails from the Port. Even after receipt of the Order dated 4 February 2000 passed by the TAMP, the process of refund was delayed up to 24 March 2000. The cheque for refund amount was issued on 31 March 2000 ignoring the interest due from 1995 onwards or from the date of final marine dues bills for concerned vessels.
- (iii). The KPT denied interest payment merely on the ground that refund application was in conformity with neither the TAMP's Order nor the FA & CAO's circular. This is not correct as the refundable amount was confirmed and / or sanctioned on 24 March 2000. On 24 March 2000 no formalities were pending; hence, payment could have been arranged on that date.
- (iv). The KPT was aware of the Order; and, hence, within a period of 30 days, the old refunds for the year 1995 and 1997 could have been finalised much earlier than 24 March 2000.
- (v). The interest accrued on Rs.1,47,321/- for seven days from 24.3.2000 to 31.3.2000 may be paid.

4. The comments received from the KPT on the representation from M/s Asia Shipping Services are summarised below:

- (i). M/s Asia Shipping Services is a regular port user and maintaining a traffic deposit account for various Port services. The party applied for refund of the balances available at their account without furnishing any details thereof pertaining to the period from 1991 onwards vide their application dated 24 November 99
- (ii). On a request made by the KPT to furnish the details, M/s Asia Shipping Services had submitted on 27 January 2000 a statement of claim for the period from 1991 onwards. On scrutiny it was observed that all the claims were adjusted for the future services excepting five voyage accounts amounting to Rs 1,47,231/- pertaining to the period from 1995 onwards. The claim was accordingly processed and a cheque was issued on 29 March 2000. The cheque was collected by the party on 31 March 2000
- (iii). The request of the party for payment of interest for the period from 24 March 2000 to 31 March 2000 i.e for seven days does not appear to be justified looking to the fact that the balances were accumulated in the deposit account as a running account and when the party had approached for refund the same had been finalised within a reasonable time on production of relevant documents.

5. M/s Asia Shipping Services has submitted its observations on the comments from the KPT which are summarised below.

- (i) It is not correct that a traffic deposit account is maintained. They arranged vessel-wise advance deposits
- (ii) It is not correct that one vessel credit balance is adjusted in next coming vessel. They do not have much volume of work and always expect the KPT to refund the balance amount.
- (iii). The cheque was not collected but handed over only on 31 March 2000
- (iv) If the application was finalised prior to 24 March 2000, then the issue of the request for interest would not have arisen

6. The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry (GCCI) has also submitted a representation relating to penal interest on delayed payments by the KPT. The GCCI has stated that the KPT has issued a circular stating that the interest payment on delayed refunds will be subject to the condition that the documents/refund application are complete in all respects. The GCCI is of the opinion that this addition will defeat the very purpose of the Order issued by the TAMP.

7. In its reply to the representation of the GCCI, the KPT has stated that in order to verify the genuineness of a refund claim, many documents are required from a user along with the refund application. Unless all the required documents are attached and complete in all respect, no action can be taken to process a refund claim. The clause added in the circular also mean that the refund application has to be submitted within the time limit prescribed under Section 55 of the MPT Act 1963. The KPT opined that the clause will also prevent any possible misuse of the Order.

8. A joint hearing in this case was held on 16 September 2000. During the joint hearing, the following submissions were made.

**M/s Asia Shipping Services**

- (i). The order of the TAMP dated 4 February 2000 relating to payment of penal interest came into force on 24 March 2000.
- (ii). They are asking for interest only for the delay after the Order came into effect

- (iii). They are not claiming for any retrospective refunds under our order.
- (iv). Payment was made by the KPT on 31 March 2000. There was delay of seven days. The KPT should pay interest for those seven days.
- (v). The KPT did not give them the facility of carry forward of balance in their account.

#### **Kandla Port Trust (KPT)**

- (i). The KPT was charging only 18% interest. But with effect from 24 March 2000 they started considering 24% interest per annum for all outstanding. They did not go for retrospective application. They applied this only on new arrivals.
- (ii). There were delays in recovery of old amount due to the Port also. But they have not charged 24% in case of such old recovery.
- (iii). If they make an exception in this case of M/s Asia Shipping Services, then they will have to consider it for all. They have not made any discrimination.

9 With reference to the totality of information collected during the processing of the case, and based on a collective application of mind, the following position emerges

- (i). The Applicant and the KPT have advanced their respective arguments in support of the processing of refund claims pertaining to the period prior to 24 March 2000. The Applicant has, however, claimed interest on the delayed refund of their claim for a period of 7 days starting from 24 March 2000 arguing that the Authority's Order in this regard had come into force with effect from that date. That being so, the question to be decided is whether penal interest is payable for the alleged delay of 7 days from 24 March 2000 caused by the KPT.
- (ii). Prior to the Authority's Order dated 4 Feb 2000, there was no provision for payment of interest by the KPT to port users in case of amount withheld / delayed refunds by the Port.
- (iii). It is to be recognised that the intention behind the Order is to prescribe a uniformity of penal interest payable bothways by port users as also by the port trusts. In other words, the prescription is to provide a level playing ground for both the sides relevant to any transaction.
- (iv). The KPT has confirmed implementation of the Authority's Order with effect from 24 March 2000. However, the KPT has indicated that, to avoid complications, it has implemented the Order prospectively from the cases arising out of vessels berthed on or after 24 March 2000. It is noteworthy that the KPT has also foregone its claim to levy penal interest receivable by it on all outstanding amounts arising out of vessels sailed out prior to 24 March 2000.
- (v). The KPT has implemented the Order in its true spirit. In any transition period, it may be logical to allow some lead-time for the implementing agency to adjust to the changes. Viewed in this perspective, the 7 days' delay in remitting the payment to the party deserves to be condoned.
- (vi). The GCCI representation against the inclusion of certain conditions by the KPT for payment of penal interest on delayed refunds appears to be without any merit. The arguments of the KPT for inclusion of a condition that the interest payment on delayed refunds will be subject to the documents / refund applications are complete in all respects appears to be reasonable and strictly in accordance with

this Authority's own prescription. The Port can process the refund claims only when such claims are complete in all respects. However, it will be fair on the part of the KPT if it notifies the Trade Users about the formalities for completing the refund and also the list of documents to be submitted along with the refund claims.

10. In the result, and for the reasons given above, the Authority rejects the representation made by M/s. Asia Shipping Services.

S. SATHYAM, Chairman  
[ADVT/III/IV/143/2000/Extv.]